चीनी की मांग में आई गिरावट आयात की नहीं जरूरत

राजेश भयानी
मुंबई, 7 मार्च

भारत में आने वाले महीनों के लिए चीनी की मांग सुस्त बने रहने के अनुमान के साथ हालात स्थिर दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी की मांग में गिरावट के परिणामस्वरूप, सरकार आयात शुल्क घटाने की जल्दबाजी में नहीं है।

भारतीय चीनी मिल संगठन (इस्मा) ने सोमवार को हुई बैठक में उत्पादन अनुमान 2.13 करोड़ टन से घटाकर 2.03 करोड़ टन कर दिया है। चीनी वर्ष 2016-17 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए इसका मूल अनुमान 2.35 करोड़ टन था। मांग में भी गिरावट आई है और खपत अनुमान को घटाकर 2.38 करोड़ टन किया गया है।

इस्मा की अध्यक्ष टी सरिता रेड्डी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हालांकि उत्पादन अनुमान घटाया गया है और मांग में कमी आ रही है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी अधिकारियों ने उद्योग के इस रुख पर सहमति जताई है कि फिलहाल आयात की अनुमति दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश में अगले सीजन के लिए दो महीनों की मांग पूरी करने के लिहाज से पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।'

वर्ष (अक्टूबर-सितंबर)	चीन उत्पादन (लाख टन)
2010-11	244
2011-12	263
2012-13	251
2013-14	244
2014-15	283
2015-16	251
2016-17*	203

* अनुमान
सोत - इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

पिछले महीने कीमतें भी स्थिर रहीं जिससे आयात के संदर्भ में जल्दबाजी नहीं दिखाना उचित है।

नोटबंदी के बाद इस्मा ने अपने खपत अनुमान को एक महीने पहले घटाकर 2.48 करोड़ टन कर दिया था और सोमवार की बैठक में इसे और घटाकर 2.38 करोड़ टन किया गया है।

अनुमान है कि आगामी सत्र (अक्टूबर 2017 से) में चीनी का अधिक उत्पादन होगा और इसके 2.5 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। साथ ही सत्र की शुरुआत 40-42 लाख टन के पिछले स्टॉक के साथ होगी जो दो महीनों की मांग को पूरा करने के लिहाज से पर्याप्त है।

रेड्डी ने कहा, 'दक्षिण भारत की चीनी मिलों ने सूखे की वजह से अपनी ऋण समस्याओं से भी सरकार को अवगत कराया है। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ऋण पुनर्गठन को लेकर गंभीरता से विचार किया जाएगा और महीने के अंत तक बकाया चीनी सब्सिडी मुहैया करा दी जाएगी।'

अप्रैल से केंद्र सरकार राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चीनी पर सब्सिडी मुहैया नहीं कराएगी जिससे राशन दुकानों पर कीमतें बढ़ सकती हैं और फिर मांग में संभावित गिरावट देखी जा सकती है।

उन्होंने कहा, 'हम मई में उत्पादन और खपत पैटर्न की समीक्षा के लिए फिर से बैठक करेंगे और सरकार को हालात से अवगत कराएंगे।'

Business Standard
8/3/17